

क्रिप्टोकॉरेंसी के वनियमन का प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान बैंकों समेत सभी वनियामक एजेंसियों को क्रिप्टोकॉरेंसी (cryptocurrency) से नपिटने हेतु किसी भी व्यक्ति या इकाई द्वारा आभासी मुद्राओं (VC) के व्यवसाय को रोकने के लिये निर्देशित किया था।

प्रमुख बिंदु

- RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को आभासी मुद्राओं में काम करने वाले लोगों की सभी सेवाओं को रोकना है।
- इसके तहत ऐसे व्यक्तियों के आभासी मुद्रा में वभिन्न गतिविधियों, जैसे- ख़ातों को बनाए रखना, पंजीकरण करना, समाशोधन करना (clearing), आभासी टोकन के माध्यम से ऋण देना, संपाश्वक (collateral) आदि को रोकना है।
- RBI और वित्त मंत्रालय ने बटिकॉइन जैसी वरचुअल क़रेंसी को पोंजी स्कीम की तरह माना है और इन्हें मान्यता नहीं दी है।

पोंजी स्कीम

- पोंजी स्कीम से आशय ऐसी फर्जी योजनाओं अथवा निवेश से है, जिसमें संचालक पुराने निवेशकों को रटिर्न नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि से देता है।
- यह एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें किसी व्यावसायिक गतिविधि या कारोबार में पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा कर एक व्यक्ति को रटिर्न के रूप में दे दिया जाता है।
- इस प्रकार यह एक चेन का रूप ले लेती है और जिसमें बाद में पैसा लगाने वाले ज्यादातर लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है।
- साथ ही नीति निर्माताओं ने यह आशंका व्यक्त की है कि क्रिप्टोकॉरेंसियाँ, फ़ैट मुद्रा के मूल्य का वैकल्पिक स्रोत होने की वजह से इसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग, तस्करी और मनी लांडरींग जैसे गैर-कानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि 'फ़ैट क्रिप्टोकॉरेंसी' एक डिजिटल मुद्रा है, जिसे भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।

क्रिप्टोकॉरेंसी (cryptocurrency) क्या है?

- यह एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसमें सुरक्षा के लिये क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसकी सुरक्षा वैशिष्ट्य के कारण इसका जाली रूप बनाना मुश्किल है।
- इसे किसी केन्द्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से यह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
- सन् 2009 में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से 'बटिकॉइन' के नाम से पहली क्रिप्टोकॉरेंसी बनाई।

क्या है फ़ैट और नॉन-फ़ैट क्रिप्टोकॉरेंसी?

- "नॉन-फ़ैट" क्रिप्टोकॉरेंसी ("non-fiat" cryptocurrency) को लेकर भारतीय रज़िर्व बैंक के साथ-साथ सरकारें भी समय-समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती हैं।
- एक 'नॉन-फ़ैट' क्रिप्टोकॉरेंसी जैसे बटिकॉइन, एक नज़ि क्रिप्टोकॉरेंसी है। जबकि 'फ़ैट क्रिप्टोकॉरेंसी' एक डिजिटल मुद्रा है जो देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
- "नॉन-फ़ैट" क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं और यह तकनीकी उन्नयन वनिशकारी साबित हो सकता है।
- यदि भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा कोई आभासी मुद्रा जारी की जाती है, तो उसे फ़ैट क्रिप्टो-क़रेंसी कहा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि सभी क्रिप्टो-क़रेंसी बटिकॉइन नहीं हैं, जबकि सभी बटिकॉइन क्रिप्टो-क़रेंसी हैं। बटिकॉइन (bitcoin), एथरॉम (ethereum) और रिपल (ripple) कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो-क़रेंसी हैं।

क्रिप्टोकॉरेंसी की लोकप्रियता के कारण

नज़िता बनाए रखने में मददगार:

- क्रिप्टोकॉरेंसी के ज़रिये लेन-देन के दौरान छद्म नाम एवं पहचान बताए जाते हैं। ऐसे में अपनी नज़िता को लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह माध्यम उपयुक्त जान पड़ता है।

एक लागत-प्रभावी विकल्प:

- क्रपिटोकॉर्सेसी में लेन-देन संबंधी लागत अत्यंत ही कम है। धरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी लेन-देन की लागत एक समान ही होती है।
- क्रपिटोकॉर्सेसी के ज़रिये होने वाले लेन-देन में 'थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन' (third party certification) की आवश्यकता नहीं होती। अतः धन एवं समय दोनों की बचत होती है।

न के बराबर हैं प्रवेश जनक बाधाएँ:

- गौरतलब है कि बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर लगभग सभी लेन-देन के लिये कई तरह के प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती है, जबकि क्रपिटोकॉर्सेसी के मामले में ऐसा नहीं है।
- वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन के लिये भी कई तरह की औपचारिकताओं से गुज़रना होता है, जबकि क्रपिटोकॉर्सेसी से होने वाले लेन-देन में इन बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था का एक विकल्प:

- बैंकिंग प्रणालियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन पर सरकार का सख्त नियंत्रण होता है।
- वहीं क्रपिटोकॉर्सेसी उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर धन के आदान-प्रदान का एक विश्वसनीय और सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है।

ओपन सोर्स पद्धति:

- गौरतलब है कि अधिकांश क्रपिटोकॉर्सेसी प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित होते हैं। इन प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हैं।
- इसका प्रभाव यह होता है कि क्रपिटोकॉर्सेसी प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार की संभावनाएँ बनी रहती हैं।

वित्तीय दंड से सुरक्षा:

- वदिति हो कि सरकारों के पास बैंक खाते को फ्रीज या जब्त करने का अधिकार है, लेकिन क्रपिटोकॉर्सेसी के मामले में वे ऐसा नहीं कर सकती हैं।
- अतः सरकार के नियंत्रण से बचाव के एक प्रभावकारी विकल्प के रूप में भी क्रपिटोकॉर्सेसी का प्रयोग किया जा रहा है।

क्रपिटोकॉर्सेसी का प्रचलन खतरनाक क्यों?

एक असुरक्षित मुद्रा:

- क्रपिटोकॉर्सेसी की सम्पूर्ण व्यवस्था के ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है और इसके हैक होने का खतरा बना रहता है।
- क्रपिटोकॉर्सेसी की सबसे बड़ी समस्या है इसका ऑनलाइन होना और यही कारण है कि क्रपिटोकॉर्सेसी को एक असुरक्षित मुद्रा माना जा रहा है।

देश की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- यह 'मुख्य वित्तीय सिस्टम' और 'बैंकिंग प्रणाली' से बाहर रहकर काम करती है। यही कारण है कि इसके स्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं।
- इस डिजिटल मुद्रा को फ़ॉर्ड, हवाला मनी और आतंकी गतिविधियों को पोषित करने वाली मुद्रा के रूप में संबोधित किया जाता रहा है।

नियंत्रण एवं प्रबंधन की समस्या:

- क्रपिटो-कॉर्सेसी से संबंधित एक बड़ी समस्या इसके नियंत्रण एवं प्रबंधन की भी है। भारत जैसे कई देशों ने अभी तक इसे मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की है, ऐसे में इसका प्रबंधन एक बड़ी समस्या है।
- आर्थिक जानकारों का भी मानना है कि इसकी तकनीकी जानकारी रखे बिना इसमें निवेश करने के भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं।

पर्यावरणीय चिंताएँ:

- गौरतलब है कि प्रत्येक बटिकॉइन लेन-देन के लिये लगभग 237 किलोवाट बजिली की खपत होती है और इससे प्रतिघंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है।

